

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का युवाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ

सीएम ने गठित की पूर्व अधिकारियों व शिक्षाविदों की **टीम** विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में युवाओं से करेगी संवाद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें इसे मेगा इवेंट से होने वाले बदलाव से अवगत कराने के लिए समिट से पूर्व अभिनव पहल की है। सीएम योगी ने सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाओं व नीतियों से युवाओं को अवगत कराने के लिए 48 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12, भारतीय पुलिस सेवा और वन सेवा के छह-छह अधिकारियों (सभी सेवानिवृत्त) के साथ 24 वरिष्ठ शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। यह टीम तीन से पांच फरवरी तक अलग-अलग विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में युवाओं से संवाद कर रोजगार से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेगी, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपयोगिता से अवगत कराएगी।

मुख्यमंत्री ने पूर्व अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों की टीम से मंगलवार को संवाद किया और उनसे अपने विजन को साझा किया। स्पष्ट कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को मिलेगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक बढ़ाने के उद्देश्य से देश-विदेश से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए



चार लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जब हमने प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली थी, तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। हमने सभी पहलुओं का अध्ययन कर मिशन मोड में काम किया। कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने के प्रयास हुए। अगले ही वर्ष जब हमने इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया तो 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके उपरान्त तीन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लगभग 4 लाख करोड़ तक के प्रस्तावों को जमीन पर उतार चुके हैं।

आगामी 10-12 फरवरी को लखनऊ में उप्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिवसीय समिट न केवल प्रदेश में औद्योगीकरण की संभावनाओं को जमीन पर उतारने वाली होगी, बल्कि प्रदेश के सामान्य नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित करने वाली भी होगी।

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ, सभी जिलों में एक साथ होगा निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 फरवरी को प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाएगा। एक दिन-एक साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में निवेश होगा। कार्यक्रम में स्थानीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के युवाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में भ्रमण कर सरकार की योजनाओं से छात्रों को अवगत कराया जाना चाहिए। जिन जिलों में कोई विश्वविद्यालय नहीं है वहां महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि नौकरी व रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन के लिए हमारे युवा अब विवश नहीं होंगे। समिट से पूर्व विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षिक संस्थानों में आप सभी का युवाओं से संवाद महत्वपूर्ण होगा। आप उप्र सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न नीतियों के माध्यम से वृहद पूंजी निवेश आकर्षित किए जाने की योजनाओं की जानकारी युवाओं को दें।

निवेश को मुकाम तक पहुंचाएंगे उद्यमी मित्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : निवेश परियोजनाओं को मुकाम तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार उद्यमी मित्रों की सेवाएं लेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत एमबीए डिग्री के साथ तकनीकी दक्षता में निपुण कुल 105 उद्यमी मित्रों की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली जाएंगी। इन्हें प्रतिमाह 70 हजार रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा, इसमें सभी भत्ते शामिल होंगे। इनकी सेवाएं फिलहाल एक वर्ष के लिए ली जाएंगी, विशेष परिस्थिति में एक वर्ष का विस्तार भी दिया जा सकता है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ इनके नियुक्त पदाधिकारी होंगे। कैबिनेट से स्वीकृति इस प्रस्ताव के बाबत शासनादेश जारी हो गया है। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार के स्तर से इन्वेस्ट यूपी के सीईओ को जारी पत्र में उद्यमी मित्रों की योग्यता, दायित्वों और मानदेय पर स्थिति स्पष्ट की गई है।

उद्यमी मित्र की न्यूनतम योग्यता 60 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीए तय की गई है। धारा प्रवाह हिंदी और अंग्रेजी बोलने के साथ-साथ कंप्यूटर और टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। विदेशी भाषा के जानकार को प्राथमिकता मिलेगी। इन्हें इंडस्ट्री, डिफेंस, एगरोस्पेस, आइटी, स्टार्टअप, हथकरघा, कृषि या किसी

- 70 हजार रुपये मासिक पर रखे जाएंगे 105 उद्यमी मित्र
- फिलहाल एक वर्ष के लिए ली जाएंगी उद्यमी मित्रों की सेवाएं

अन्य क्षेत्र में कार्य का अनुभव या इससे जुड़ा ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा 25 से 40 वर्ष है। कुल सृजित होने वाले 105 पदों में, जिलों के लिए 70 पद, इन्वेस्ट यूपी मुख्यालय के लिए 10 और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए 25 पद सृजित होंगे। उद्यमी मित्रों को प्रतिमाह मूल नियत भत्ते के रूप में 30 हजार रुपये मिलेंगे, मकान किराया भत्ता के रूप में 10 हजार, निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए 10 हजार का अतिरिक्त भत्ता और यात्रा अथवा परियोजना स्थल के भ्रमण के लिए प्रतिमाह 20 हजार का अतिरिक्त भुगतान होगा। टेबलेट क्रय करने के लिए 15 हजार का एकमुश्त भुगतान होगा। भर्ती के लिए आवेदन इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर आनलाइन देना होगा। इनका मुख्य कार्य आवंटित क्षेत्र में निवेशकों के साथ परियोजना स्थल का दौरा करना, निवेश प्रक्रिया और उससे जुड़े एनओसी जारी करने के साथ-साथ निवेशकों से जुड़ी प्रत्येक समस्या का समाधान करना होगा।